(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया था, इन्हें पूरा करने में कितना विलंब हो गया है तथा इस विलंब के परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के काम में तेज़ी लाने के लिए सरकार क्या समयबद्ध कार्यक्रम बना रही है?

रेल मंत्री (श्री सी॰के॰ जाफर शरीफ): (क) निर्माण कार्यक्रम में शामिल की गई परियोजनाओं पर निर्धारित कार्यक्रम तथा धन की उपलब्धता के अनुसार प्रगति हो रही है। प्राथमिक वाली परियोजनाओं की अलग से कोई सूची नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उपनगरीय रेल सेवाओं की समय-सारिणी का पालन किया जाना

7192. **श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उप-नगरीय रेल सेवा में रेलगाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान के समय का प्रबंध ठीक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी॰के॰ जाफर शरीफ): (क) और (ख) उपनगरीय गाड़ियों का समयपालन कुल मिलाकर संतोषजनक है, तथापि, उपनगरीय गाड़ियां परिचालनिक तथा रेलों के नियंत्रण से बाहर के कारकों यथा आंदोलनों, शरारती गतिविधियों, समयपारों पर बाधाओं आदि के कारण कभी-कभी विलंब से चलती हैं, चूंकि गाड़ियां कम अंतराल पर चलती हैं, एक गाड़ी की आंशिक रुकावटी से अन्य गाड़ियों पर, जो पीछे-पीछे चलती हैं, चक्र प्रभाव पड़ता है। उपनगरीय गाड़ियों के चालन पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है और समयपालन को बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया जाता है।

रेलवे की आय को बढ़ाने के लिए योजनाएं

7193. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे की आय को बढ़ाने तथा राजस्व की हानि को रोकने के लिए नई प्रविधियां अपनाकर संचालन संबंधी लागत तथा खर्चे को कम करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी परामर्शदाता संगठन के माध्यम से कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम प्राप्त हुआ है?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ): (क) और (ख) आमदनी बढ़ाना तथा परिचालिक लागतों/खर्चों में कमी करना, रेलों का एक सतत प्रयास है। इसके लिए भारतीय रेलें, अतिरिक्त यातायात जुटाने के लिए कारगर विपणन नीतियां बनाने, पण्यों के टिकट यात्रा पर नियंत्रण करने, बकायों की प्रभावी रूप से वसूली करने, गतिविधियों की शून्य आधारित समीक्षा करने, ऊर्जा संरक्षण, परिसंपत्तियों के उपयोग में सुधार सभी लाइन तथा गैर-लाइन संबंधी गतिविधियों की लागत पर नियंत्रण/उनमें कमी आदि करने जैसे विभिन्न उपाय कर रही है।

इसके परिणामस्वरूप, परिचालन अनुपात में 1990-91 के 92.0 प्रतिशत से 1994-95 में 83.5 प्रतिशत (लगभग) तक सुधार कर पाना और संचालन व्ययों को नियंत्रित कर पाना संभव हुआ है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	वास्तविक	कमी बेशी (वास्तविक -ब.अ.)
1990-91	8241	8234	-7
1991-92	9180	9209	+29
1992-93	10460	10480	+20
1993-94	11955	11760	-195
1994-95	13307	12763*	-544

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Free rail passes and medical facilities to dependant guardians of Railway employees

7194. SHRI SANGH PR1YA GAUTAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what are the facilities extended to the dependant guardians and other family members

of the Railway employees, as per the existing rules;

(b) whether it is a fact that the dependant guardians of the employees are not provided primary facilities of free railway travel pass and free medical treatment in the railway hospitals;

(c) it so, what are the reasons therefor,

(d) whether Government propose to extend such facilities to the dependant guardians of railway employees; and

(e) if so, by when and whether the Members of Parliament and employees' untms have sent representations in this regard?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) to (e) Free medical facilities and Privilege Passes/ Privilege Ticket Orders for rail travel are available to family members'of the railway employees and their dependant relatives (if father is not alive), as defined in the Railway Servants (Pass) Rules, 1986. Father is not included as a dependant relative under the Pass Rules. Representations have been received for inclusion of father in Privilege Passes/Privilege Ticket Orders. There is no proposal to enlarge the scope of this facility. However, dependent parents are provided with concessional medical facilities in Railway Hospitals/Health Units.

मेहता ऑफसेट वर्क्स, नई दिल्ली द्वारा रेलवे के वार्षिक प्रतिवेदनों का मुद्रण

7195. श्री शिव प्रसाद चनपुरिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदनों को मेहता ऑफसेट वर्क्स, नई दिल्ली से मुद्रित कराए जाने के कारण है, जबकि भारतीय रेलवे के अंतर्गत ग्यारह सामान्य मुद्रणालय तांकि ग्यारह टिकट मुद्रणालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन के मुद्रण के लिए मेहता ऑफसेट वर्क्स, नई दिल्ली को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) क्या रेलवे के मुद्रणालयों में इस प्रतिवेदन का मुद्रण करना संभव नहीं था, यदि हां, तो क्या देश के अन्य मुद्रणालयों की तुलना में उक्त मुद्रण के सस्ता होने के संबंध में कोई जांच कराई गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ): (क) से (ग) भारतीय रेल की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा माननीय संसद सदस्यों को अन्य बजट प्रलेखों के साथ परिपत्रित किए जाने के अलावा देश के भीतर और विदेशों में स्थित महत्वपूर्ण एजेन्सियों यथा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय रेल संघ (यू.आई.सी.), एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (एस्कैप), विभिन्न विश्व रेलवे प्रणालियों आदि को व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय रेल की छवि प्रतिबिम्बित करती है। अत: इस प्रकाशन की गुणवत्ता और रूप सज्जा सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसी गुणवत्ता वाले कार्य को जिसे रेलों की अपनी सुविधाओं (रेलवे मुद्रणालय) के विशाल कार्यभार के साथ-साथ कड़ी समय अनुसूची के अन्तर्गत निष्पादित किया जाना अपेक्षित हो, अवसंरचना परिसीमाओं के कारण वार्षिक रिपोर्ट और लेखे-1993-94 के मुद्रण का कार्य व्यावसायिक संस्थान (मैसर्स मेहता ऑफसेट वर्क्स, नई दिल्ली) को सौंपा गया था, जैसा कि 1974 से हो रहा है। विपणन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दिल्ली के विभिन्न "क" श्रेणी मुद्रकों में से मैसर्स मेहता ऑफसेट वर्क्स, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया प्रस्ताव निम्नतम था, अत: यह मुद्रण कार्य उन्हें प्रदान किया गया था, इस फर्म को वार्षिक रिपोर्ट और लेखे - 1993-94 की 5800 प्रतियां मुद्रित कराने के लिए 2,57,000/- रु. (रुपये दो लाख सत्तावन हजार केवल) का भुगतान किया गया था। प्रस्ताव आमंत्रित करने वाली सूचना को, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कड़ी समय अनुसूची के कारण विदप्रनि द्वारा अनुमोदित दिल्ली के "क" श्रेणी मुद्रकों तक सीमित रखना पड़ा था।

गुजरात में कोयले को लाने-ले जाने के लिए वैगनों के कोटे में वृद्धि किया जाना

7196. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कोयले को लाने-ले जाने के लिए वैगनों के कोटे को बढ़ाने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे अंतिम रूप कब तक दे दिया जाएगा?